

दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय की तिथि : 20 मई, 2024

मध्य.या. 321/2024

मेसर्स के.एल.डी. क्रिएशन इन्फ्रास्ट्रक्चर
प्राइवेट लिमिटेड

.....याचिकाकर्ता

द्वारा: सुश्री अनुराधा पांडा, अधिवक्ता

बनाम

राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास
निगम सीमित

.....प्रत्यर्थी

द्वारा: अधिवक्तागण सुश्री राजदीपा बेहुरा,
श्री फिलोमोन कानी, सुश्री नेहा
डोबरियाल, सुश्री सिमरत कौर सरीन,

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति श्री अमित बंसल

अमित बंसल, न्या. (मौखिक)

1. यह याचिका मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (इसके बाद 'अधिनियम') की खंड 11 के अधीन दायर की गई है, जिसमें पक्षों के बीच विवादों पर निर्णय लेने के लिए एक स्वतंत्र एकल मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग

की गई है। पक्षकारों के बीच विवाद प्रत्यर्थी-राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एन.एच.आई.डी.सी.) द्वारा 18 जुलाई, 2023 को जारी एक समाप्ति सूचना से उत्पन्न हुए हैं।

2. वर्तमान याचिका में नोटिस 5 मार्च 2024 को जारी किया गया था।
3. विवाद की पृष्ठभूमि यह है कि याचिकाकर्ता को "राष्ट्रीय राजमार्ग 108 बी पर अगरतला-खोवाई खंड के डिजाइन किमी 19.300 से किमी 31.300 (कुल लंबाई: 12.000 किमी) तक सड़क के पुनर्वास और उन्नयन कर त्रिपुरा राज्य में ईपीसी आधार (पैकेज-11) (इसके बाद 'ईपीसी अनुबंध') में पेव्ड शोल्डर वाली दो लेन में बदलने" का अनुबंध दिया गया था। उक्त ई.पी.सी. अनुबंध के अनुसार याचिकाकर्ता को निर्दिष्ट तकनीकी मानकों के अनुपालन में और स्वीकार्य समय सीमा के भीतर निर्माण कार्य को निष्पादित करना था।

4. याचिकाकर्ता का तर्क है कि ई.पी.सी. अनुबंध ने स्पष्ट रूप से प्रत्यर्थी की ओर से कुछ दायित्वों को सूचीबद्ध किया है। विशेष रूप से, प्रत्यर्थी को 'नियत तिथि' से पहले परियोजना राजमार्ग की कुल लंबाई के कम से कम 90 प्रतिशत के लिए बोझ-मुक्त 'मार्गाधिकार' (आरओडब्ल्यू) प्राप्त करना आवश्यक था, जिसे बाद में 8 जून, 2021 घोषित किया गया था। इसके अतिरिक्त, प्रत्यर्थी को ई.पी.सी. अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के 30 दिनों के भीतर याचिकाकर्ता को इस आर.ओ.डब्ल्यू. का 90 प्रतिशत प्रदान करना आवश्यक था। वर्तमान याचिका में, याचिकाकर्ता द्वारा आगे यह दावा किया गया है कि प्रत्यर्थी ने उपरोक्त

संविदात्मक दायित्वों का पालन नहीं किया, और याचिकाकर्ता को अपने काम को निष्पादित करने से रोकने में कई बाधाएं थीं।

5. याचिकाकर्ता द्वारा आगे यह दावा किया जाता है कि प्रत्यर्थी ने याचिकाकर्ता को भुगतान करने के लिए अपनी एसएपी प्रणाली को सही करने से इनकार कर दिया, जो उसके द्वारा उठाए गए विभिन्न चरण भुगतान विवरणों के अधीन सही था, जिसकी गणना ईपीसी अनुबंध की अनुसूची बी में उल्लिखित कार्य के दायरे के अनुसार की गई थी। याचिकाकर्ता के अनुसार, इस गैर-भुगतान का याचिकाकर्ता की आर्थिक स्थिति पर व्यापक प्रभाव पड़ा, जिससे उसकी श्रमशक्ति और संसाधन जुटाने की योग्यता प्रभावित हुई।

6. उपर्युक्त मुद्दों के अलावा, यह भी दावा किया जाता है कि प्रत्यर्थी ने याचिकाकर्ता के बिलों और उसके तकनीकी डिजाइनों को मंजूरी देने में देरी की, जिससे काम को पूरी तरह से निष्पादित करने की उसकी योग्यता बाधित हुई। याचिकाकर्ता के अनुसार, इससे ऐसी स्थिति पैदा हुई कि अनुबंध के अधीन अपने कर्तव्यों को लगन से निभाने के प्रयास के बावजूद, याचिकाकर्ता को ऐसा करने से रोक दिया गया था। नतीजतन, याचिकाकर्ता ईपीसी अनुबंध में दिए गए लक्ष्यों को पूरा करने में असमर्थ था। याचिकाकर्ता का यह मामला है कि प्रत्यर्थी ने अपने संविदात्मक दायित्वों का पालन करने में विफल रहने की जवाबदारी खुद से हटाने की दृष्टि से, याचिकाकर्ता पर काम की धीमी प्रगति, लक्ष्यों को पूरा न करने और अन्य परिणामी विफलताओं का आरोप लगाते हुए

नियमित पत्रों के साथ उपचार नोटिस भेजना शुरू कर दिया, जो संविदात्मक रूप से बाध्य विल्लंगम-मुक्त आरओडब्ल्यू के गैर-प्रावधान से हुआ था।

7. हालाँकि, प्रत्यर्थी स्वीकार करता है कि उसने समय सीमा बढ़ाई थी, लेकिन याचिकाकर्ता के अनुसार यह केवल एक भ्रामक उपाय था, जिसमें अंतर्निहित गलतियों को ठीक नहीं किया गया था, जिससे याचिकाकर्ता विफल हो गया। जब याचिकाकर्ता कार्य स्थल की अनुपलब्धता और प्रत्यर्थी के कारण नकदी प्रवाह संकट के कारण लक्ष्य को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा था, तो प्रत्यर्थी ने याचिकाकर्ता को पालन न करने वाला घोषित कर दिया, जिससे उसे किसी भी निविदा में भाग लेने से रोक दिया गया। इसके बाद, प्रत्यर्थी ने 24 फरवरी, 2022 को याचिकाकर्ता को कार्यों की धीमी प्रगति, लक्ष्य को पूरा न करने और अन्य परिणामी विफलताओं के लिए बर्खास्त करने के इरादे का नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता का दावा है कि उसने 9 मार्च, 2022 को समाप्ति सूचना का उत्तर दिया और उसके बाद ई.पी.सी. अनुबंध और विस्तारण के अनुसार काम जारी रखा।

8. याचिकाकर्ता द्वारा यह कहा गया है कि 14 फरवरी, 2023 को ई.पी.सी. अनुबंध की अवधि समाप्त होने के बाद, याचिकाकर्ता ने समय बढ़ाने का अनुरोध किया, जिसे प्रत्यर्थी द्वारा 14 मार्च, 2023 के पत्र के माध्यम से विधिवत मंजूरी दी गई थी। इसके बाद, यह दावा किया जाता है कि जब याचिकाकर्ता अनुबंध का निष्पादन कर रहा था, तो प्रत्यर्थी ने बिना कोई नोटिस जारी किए और

याचिकाकर्ता कोई प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिए बिना 18 जुलाई, 2023 को ईपीसी अनुबंध को अचानक समाप्त कर दिया।

9. 27 जुलाई, 2023 के समाप्ति नोटिस के उत्तर के माध्यम से, याचिकाकर्ता ने ईपीसी अनुबंध के खंड 26.2 के अधीन सुलह का सहारा लिया था। हालाँकि, प्रत्यर्थी इसे स्वीकार करने में विफल रहा और उक्त परियोजना के लिए बोली आमंत्रित करने के लिए एक नया नोटिस जारी करने के लिए आगे बढ़ा। तदनुसार, याचिकाकर्ता ने एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए वर्तमान याचिका दायर की है।

10. प्रत्यर्थी की ओर से जवाब दाखिल किया गया है। जवाब में, प्रत्यर्थी ने ई.पी.सी. अनुबंध में मध्यस्थता खंड के अस्तित्व पर आपत्ति नहीं जताई है।

11. न्यायालय ने सभी पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और अभिलेख का अध्ययन किया है।

12. शुरुआत में, ई.पी.सी. अनुबंध में निहित विवाद समाधान, सुलह और मध्यस्थता (खंड 26) के खंड का संदर्भ दिया जा सकता है। उक्त खंड निम्नानुसार उद्धृत किया गया है:

"26.1 विवाद का समाधान

(क) पक्षों के बीच इस समझौते (इसकी व्याख्या सहित) के अधीन या उससे बाहर या उसके संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के विवाद, मतभेद या विवाद, और इस तरह किसी भी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को लिखित रूप में अधिसूचित किया जाएगा, ("विवाद") शुरुवात में ही, खंड 26.2 में

निर्धारित सुलह प्रक्रिया के अनुसार सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने का प्रयास किया जाएगा।

(ख) दोनों पक्ष इस समझौते के अधीन या उसके संबंध में उत्पन्न होने वाले सभी विवादों को तुरंत, समान और सद्भावपूर्ण ढंग से हल करने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयासों का उपयोग करने के लिए सहमत हैं, और आगे किसी भी विवाद से संबंधित सभी गैर-विशेषाधिकार प्राप्त अभिलेख, सूचना और जानकारी सामान्य व्यावसायिक समय के दौरान एक-दूसरे को प्रदान करने के लिए सहमत हैं।

26.2 सुलह

पक्षों के बीच किसी भी विवाद की स्थिति में, कोई भी पक्ष प्राधिकरण के इंजीनियर, या ऐसे अन्य व्यक्ति को मध्यस्थता करने और पक्षों को एक सौहार्दपूर्ण समझौते पर पहुंचने में सहायता करने के लिए बुला सकता है जिन पर पक्ष पारस्परिक रूप से सहमत हो सकते हैं। सुलहकर्ता द्वारा या सुलहकर्ता के हस्तक्षेप के बिना मध्यस्थता करने में विफल रहने पर, किसी भी पक्ष को इस तरह के विवाद को सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए प्राधिकरण के अध्यक्ष और ठेकेदार के निदेशक मंडल के अध्यक्ष को भेजे जाने की आवश्यकता हो सकती है, और इस तरह के संदर्भ पर, उक्त व्यक्ति विवाद पर चर्चा करने और सौहार्दपूर्ण ढंग से समाधान करने का प्रयास करने के लिए संदर्भ की तिथि से 7 (सात) कार्य दिवसों के बाद नहीं मिलेंगे। अगर ऐसी बैठक (तीस) कार्य दिवस अवधि के भीतर नहीं होती है या बैठक के 30 (तीस) दिनों के भीतर विवाद का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा नहीं किया जाता है या विवाद का समाधान नहीं किया जाता है जैसा कि खंड 26.1 में निर्दिष्ट लिखित सूचना के 30 (तीस) दिनों के भीतर समझौते की लिखित शर्तों पर हस्ताक्षर करने से स्पष्ट होता है या ऐसी लंबी अवधि जो पक्षों द्वारा पारस्परिक रूप से स्वीकार्य हो, कोई भी पक्ष खंड 26.3 के प्रावधानों के अनुसार विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित कर सकता है, लेकिन इस तरह के मध्यस्थता का सहारा लेने से पहले, पक्ष ऐसे विशेषज्ञों के पैनल द्वारा तय की गई प्रक्रिया के अनुसार प्राधिकरण द्वारा स्थापित स्वतंत्र विशेषज्ञों की सुलह समितियों द्वारा सुलह का पता लगाने के लिए सहमत होते हैं और प्राधिकरण द्वारा अपनी वेबसाइट पर अधिसूचित किया जाता है, जिसमें बाद के संशोधन भी शामिल हैं। सुलह की कार्यवाही के सफल होने की स्थिति में, विवाद के पक्षकार लिखित समाधान समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे

और सुलहकर्ता इसे प्रमाणित करेंगे। इस तरह का समझौता मध्यस्थता अधिनियम की धारा 73 के अधीन पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा। । सुलह समिति के स्तर पर भी सुलह प्रक्रिया की विफलता के मामले में, कोई भी पक्ष खंड 26.3 के प्रावधानों के अनुसार विवाद को मध्यस्थता के लिए भेज सकता है।"

26.3 मध्यस्थता

(क) पक्षों के बीच कोई भी विवाद जो समझौते में उपलब्ध/निर्धारित तंत्र द्वारा अनसुलझा रहता है, चाहे कोई भी दावा राशि हो, जिस पर पक्षों द्वारा सहमति नहीं बनी हो/समझौता नहीं हुआ हो, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम के अनुसार मध्यस्थ न्यायाधिकरण को भेजा जाएगा।

(ख) हटा दिया गया।

(ग) मध्यस्थ न्यायाधिकरण एक तर्कपूर्ण पंचाट ("पंचाट") देगा। इस अनुच्छेद 26 के अनुसार आयोजित किसी भी मध्यस्थता में दिया गया कोई भी पंचाट अंतिम होगा और बनने की तिथि से पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा, और ठेकेदार और प्राधिकरण सहमत हैं और बिना किसी देरी के इस तरह के पंचाट को पूरा करने का वचन देते हैं।

(घ) ठेकेदार और प्राधिकरण इस बात पर सहमत हैं कि ठेकेदार और/या प्राधिकरण, जैसा भी हो, और उनकी संबंधित संपत्तियों के विरुद्ध एक पंचाट लागू किया जा सकता है।

(ङ) यह समझौता और पक्षों के अधिकार और दायित्व पूर्ण रूप से लागू और प्रभावी रहेंगे, इसके अधीन किसी भी मध्यस्थता कार्यवाही में निर्णय लंबित रहेगा। इसके अलावा, पक्ष बिना किसी शर्त के स्वीकार करते हैं और सहमत होते हैं कि उनके बीच किसी भी विवाद के बावजूद, प्रत्येक पक्ष इस अनुच्छेद के अनुसार विवाद का समाधान होने तक अपने-अपने दायित्वों के पालन के साथ आगे बढ़ेगा।

(च) जिस पक्ष के विरुद्ध पंचाट दिया गया है, वह किसी भी कारण से न्यायालय में पंचाट को चुनौती देता है, तो वह विवाद के अंतिम निपटारे तक पंचाट के 75 प्रतिशत (पचहतर प्रतिशत) के बराबर राशि के लिए दूसरे पक्ष को अंतरिम भुगतान करेगा। उपरोक्त राशि का भुगतान उपरोक्त राशि के 120% (एक सौ बीस प्रतिशत) के बराबर राशि के लिए अपरिवर्तनीय बैंक गारंटी प्रस्तुत करने पर तुरंत किया जाएगा। विवाद के अंतिम निपटारे पर, उपरोक्त अंतरिम भुगतान को समायोजित किया जाएगा और भुगतान या

वापस की जाने वाली किसी भी शेष राशि का भुगतान या वापसी, जैसा भी हो, अंतरिम भुगतान की तिथि से ऐसी शेष राशि के अंतिम निपटारे की तिथि तक प्रति वर्ष 10 प्रतिशत (दस प्रतिशत) की दर से गणना की गई ब्याज के साथ किया जायेगा।”

13. उपरोक्त खंडों के अवलोकन से पता चलेगा कि पक्षों के बीच सुलह विफल होने की स्थिति में, पक्षों के बीच विवादों को मध्यस्थता के लिए भेजा जा सकता है। यही व्याख्या ई.पी.सी. अनुबंध के खंड 26.3 (क) के अनुरूप होगी जिसमें विशेष रूप से यह प्रावधान किया गया है कि पक्षों के बीच किसी भी अनसुलझे विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजा जा सकता है। उक्त खंड यह सुनिश्चित करता है कि जब सौहार्दपूर्ण समाधान और सुलह के प्रयास समाप्त हो गए हैं तो विवाद समाधान के लिए एक स्पष्ट मार्ग है। याचिकाकर्ता, खंड 26.2 के अनुसार सुलह प्रक्रिया को समाप्त करने के बाद, अब अधिनियम और ई.पी.सी. अनुबंध की शर्तों के अनुसार अनुबंध से उत्पन्न विवादों पर निर्णय लेने के लिए एक स्वतंत्र एकल मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग करने का हकदार है।

14. इस अधिनियम को मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा संशोधित किया गया था और उक्त संशोधन ने अधिनियम की खंड 11 (6क) को पेश किया था। **बी.एस.एन.एल. बनाम नॉर्टेल नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड**, (2021) 5 एस.सी.सी. 738 में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार, उक्त संशोधन भारत के विधि आयोग की 246वीं रिपोर्ट की सिफारिशों पर आधारित था। इसके अलावा, **बी.एस.एन.एल.** (उपरोक्त) ने यह भी कहा कि

मध्य.या. 321/2024 **पृष्ठ सं. 8**

अधिनियम में संशोधन का प्रभाव यह था कि यदि मध्यस्थता समझौते का अस्तित्व विवाद में नहीं था, तो अन्य सभी मुद्दों को निर्णय लेने के लिए मध्यस्थ न्यायाधिकरण पर छोड़ दिया जाएगा।

15. इसलिए, न्यायालय की भूमिका एक वैध मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व को सत्यापित करने तक सीमित है। एक बार जब न्यायालय पुष्टि करता है कि मध्यस्थता समझौता मौजूद है, तो वह अन्य मुद्दों पर विचार करने से बचती है, जिनका निर्णय मध्यस्थ न्यायाधिकरण या एकमात्र मध्यस्थ द्वारा किया जाना है।

16. उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए, पक्षों के अधिवक्ता संयुक्त रूप से प्रस्तुत करते हैं कि दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र, दिल्ली उच्च न्यायालय (इसके बाद 'डी.आई.ए.सी.' के रूप में संदर्भित) के तत्वावधान में एकल मध्यस्थ नियुक्त किया जा सकता है। पक्षकारों के सभी अधिकारों और तर्कों को विद्वान एकल मध्यस्थ द्वारा निर्णय लेने के लिए छोड़ा जाता है।

17. तदनुसार, श्री एमिएट एंडले, अधिवक्ता [+ 91-9811151686] को पक्षों के बीच विवादों पर निर्णय लेने के लिए एकल मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया जाता है। मध्यस्थता डी.आई.ए.सी. के तत्वावधान में आयोजित की जाएगी।

18. विद्वान मध्यस्थ का पारिश्रमिक डी.आई.ए.सी. की शुल्क अनुसूची के अनुसार होगा।

19. इस आदेश की प्रति सचिव, डी.आई.ए.सी. को ईमेल आईडी - delhiarbitrationcentre@gmail.com पर भेजी जाए।

20. तदनुसार, याचिका का निपटान किया जाता है।

अमित बंसल
(न्यायमूर्ति)

20 मई, 2024
आरटी

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।